रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 27 अगस्त, 1983/5 भाद्रपद, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन खेती एवं परिवेश संरक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 जून, 1983

संख्या एफ०टी०एस०(ए०)3-1/81.—हिमाचल प्रदेश परिरक्षण अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम संख्यांक 28) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कथित अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, सहर्ष निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

हिमाचल प्रदेश भू-संरक्षण नियम, 1983

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) ये नियम हिमाचल प्रदेश भू-संरक्षण नियम, 1983 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम तत्काल प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं**.—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश भू-संरक्षण अधिनियम, 1978 (1978 का 28) अभिप्रेत है ;

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) "मुख्य अरण्यपाल" से हिमाचल प्रदेश के मुख्य अरण्यपाल अभिप्रेत है ;
(घ) "वन मण्डलाधिकारी" से क्षेत्रीय वन मण्डल का प्रभारी वनाधिकारी, अभिप्रेत है;
(ङ) "परिक्षेत्राधिकारी" से क्षेत्रीय वन परिक्षेत्र का प्रभारी वनाधिकारी अभिप्रेत है ;
(च) "वन रक्षक" से क्षेत्रीय वन बीट का प्रभारी वन रक्षक अभिप्रेत है;
(छ) "प्रपत्र" से इन नियमों से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है ;
(ज) "पदावली" वास्तविक घरेलू अथवा कृषिक प्रयोजन के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आएंगे :—

(I) निर्माण कार्य हेतु इमारती लकड़ी या राजस्व सम्पदा से बाहर जिसमें भूमि स्थित है, घास के अतिरिक्त किसी वन उपज का हटाया जाना और प्रयोग ;

(II) स्थानीय घरेलू उपयोग हेतु काठ कोयले के विनिर्माण के अतिरिक्त ईंटें बनाने, कत्थे के विनिर्माण या अन्य किसी विनिर्माण प्रक्रिया हेतु ईन्धन का प्रयोग; और

3. **धारा 4, 5 और 6 के अधीन अधिसूचना/आदेश जारी करने से पूर्व धारा 7 के अधीन जांच-पड़ताल करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया**.—(क) किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा 4, 5 या 6 के अधीन अधिसूचना जारी करने से पूर्व मुख्य अरण्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी द्वारा, ऐसी अधिसूचना जारी करने हेतु तथ्यों को अभिनिश्चित करने के लिए, जांच पड़ताल की जायेगी।

(ख) कथित अधिकारी अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा और अन्य मामलों के साथ निम्नलिखित पहलुओं का परीक्षण कर सकता है :—

(1) क्षेत्र की स्थिति,
(2) क्षेत्र का स्वरूप तथा दशा,
(3) वर्तमान भू-उपयोग पद्धति तथा उनका सामान्य भू-गत जल स्तर पर प्रभाव,
(4) जल तथा वायु कटाव का विस्तार और मात्रा तथा कटाव के कारण,
(5) निर्वन्धन अधिरोपित किए जाने के सम्बन्ध में जनता की मनोवृति,
(6) क्या वर्तमान प्रबन्ध भू-स्तर बनाए रखने और सुधार करने के लिए समुचित है या नहीं।

(ग) और या अपनी जांच-पड़ताल को सम्पत्ति, भूमि और पेड़ों की बढ़ौतरी की हुई समस्त क्षति पर आधारित कर सकता है, जो कि बाढ़ों या अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के कारण हुई क्षति के सम्बन्ध में किए गए किसी अध्ययन के परिणामस्वरूप निर्धारित की गई हो।

(ङ) राज्य सरकार अपना समाधान करने के पश्चात् धारा 4, 5 या 6 के अधीन 30 वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु किसी कार्य को अस्थायी रूप से विनियमित, निर्वन्धित या प्रतिविध्य करने हेतु अधिसूचना जारी कर सकती है ।

4. **धारा 4 तथा 5 के अधीन निषिध्य क्षेत्रों से वनोपज को हटाने के लिए अनुज्ञापत्र देने हेतु प्रक्रिया**:—

(1) **वास्तविक घरेलु तथा कृषि प्रयोजनों हेतु :**

(क) ईंधन तथा चारे के वास्तविक घरेलु उपयोगों के लिए वनोपज के प्रयोग पर कोई निर्वन्धन नहीं होगा।

(ख) स्वामी अपने वास्तविक घरेलु तथा कृषिक प्रयोगों हेतु अधिनियम की धारा 4 और 5 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और सीमा के अनुसार वृक्ष गिरा सकते हैं।

(ग) वास्तविक घरेलु तथा कृषिक उपयोग हेतु गिराए जाने के लिए अनुज्ञात वृक्ष, मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश के निर्देशों के अनुसार चिह्नित किए जायेंगे।

(घ) स्वामी, बिना आज्ञा के गिराये वृक्षों की लिखित सूचना बीट वन रक्षक के माध्यम से सम्बन्धित प्रक्षेत्राधिकारी को भेजेगा । प्रक्षेत्राधिकारी ऐसी सूचना की प्रति वन मण्डलाधिकारी को उसके रिकार्ड हेतु भेजेगा ।

(ङ) बीट रक्षक, धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अनुज्ञा से घरेलु तथा कृषिक प्रयोगों के लिए किए गए या बिना आज्ञा के ऐसे सभी गिरान का रजिस्टर म उचित रिकार्ड रखेगा और ऐसे गिराए गए ठूंठों पर अपने हथोड़े का चिह्न अंकित करेगा। समय-समय पर ऐसे वृक्षों से प्राप्त माल उस द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकता है जब तक प्राप्त माल उस प्रयोजन हेतु उपभुक्त न हो जाए जिसके लिए वह रूपांतरित किया गया है। ऐसे वृक्षों से प्राप्त माल के किसी भी हिस्से को निर्यात करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

(2) **विक्रय हेतु**:

(क) स्वामी द्वारा विक्रय हेतु सभी प्रकार की प्रजातियों के वृक्षों का गिरान, अधिनियम की धारा. 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा विहित क्रम में किया जायेगा।

(ख) विक्रय हेतु वृक्षों को हटाने की अनुज्ञा विभिन्न कृत्यकारियों द्वारा ऊपर निर्दिष्ट अधिसूचना के अधीन विहित परिसीमा के अनुसार प्रदान की जायेगी।

(ग) स्वामी द्वारा वृक्ष गिराने तथा वनोपज हटाने के लिए प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) वह क्षत्र जहां से स्वामी द्वारा वृक्ष बेचने तात्पर्यत है, नायब-तहसीलदार से अन्युन पद के राजस्व अधिकारी द्वारा एजेण्ट के नाम निर्देशित की उपस्थिति में सीमांकित किया जायेगा परन्तु जहां नायब-तहसीलदार नियुक्त नहीं है, क्षेत्र का सीमांकन फील्ड कानूनगो द्वारा किया जायेगा।

(ङ) वृक्षों का वन वर्धनीय चिह्नीकरण, मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों तथा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जायेगा। बगीचा लगाने के प्रयोजनार्थ भी क्षेत्रों में पूर्ण गिरान की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

(च) वृक्षों के गिराने की अनुज्ञा और वन उपज के एकत्रीकरण या हटाने के लिए अनुज्ञापत्र वन मण्डल अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

(छ) गिरान अनुज्ञा/अनुज्ञापत्र जारी करते समय वन मण्डलाधिकारी ऐसे निर्बन्धन तथा शर्तें जिन्हें वह वन संरक्षण के हित में तथा निष्कासित वनोपज का दुरुपयोग न होने में अपेक्षित समझे, अधिरोपित कर सकता है। वन मण्डल अधिकारी उन वृक्ष प्रजातियों को भी दर्शायेगा जो कि गिराए गए वृक्षों की क्षति पूरक पौधारोपण म लगाए जायेंगे जैसे कि नियम 4 (ग) में निर्दिष्ट है।

(ज) हिमाचल प्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम, 1982 के उपबन्ध तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए नियम वृक्षों के विक्रय पर लागू होंगे।

(झ) वन मण्डल अधिकरी वृक्षों के गिरान की आज्ञा जारी करते समय पौधों की संख्या तथा प्रजातियां जो कि प्रतिपूरक रोपण में लगाई जायेगी उपदर्शित कर सकता है जैसा कि नियम 4(ग) में उपबंधित है।

(3) **प्रतिपूरक रोपण**:

(क) घरेलु या कृषिक या विक्रय के लिए वृक्षों का गिरान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, गिराए गए वृक्ष के बदले कम से कम तीन वृक्ष रोपित करने होंगे। यदि ऐसे क्षेत्रों में फल बगीचा रोपित किया जाता है तो भी वह भी राज्य उद्यान विभाग द्वारा क्षेत्र के पूर्ण भाग म वृक्षारोपण के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार लगाया जायेगा। ऐसे रोपित पौधों की सफलता का उत्तरदायित्व स्वामियों का होगा जिसका निरीक्षण वन उद्यान विभाग के कर्मचारी वृन्द समय-समय पर किया जायेगा।

(ख) वन मण्डल अधिकारी स्वामी से प्रतिपूरक रोपण के कार्यान्वयन हेतु रोपित किए जाने वाले प्रत्येक पौधे हेतु उस से अनाधिक राशि जमा कराने की अपेक्षा कर सकता है ताकि पौधे लगाए जा सकें, यदि स्वामी गिरान के एक वर्ष के भीतर गिरान किए गये प्रत्येक पेड़ के स्थान पर 3 पौधे लगाने में असफल रहता है।

(ग) ऐसे स्वामियों को जो अपनी निजी भूमि से वृक्षों का विक्रय करते हैं को आगामी 10 वर्षों के लिए सरकारी वनों से अधिकारधारी मूल्य पर कोई वृक्ष नहीं दिया जाएगा।

(ध) बिरोजा निस्सारण कार्य वन मण्डलाधिकारी की लिखित अनुज्ञा से, जो मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा, निस्सारण अवधि, अपछेद संख्या, लम्बाई, चौड़ाई तथा अपछेदों की गहराई और अन्य सम्बन्धित मामलों के लिए समय समय पर जारी निदेशों के अनुसार होगी, किया जाएगा ।

(ङ) निस्सारित बिरोजा, च्यावन क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति द्वारा, वन मण्डलाधिकारी से बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यात अनुज्ञापन किए बिना हटाया/निर्यात नहीं किया जाएगा ।

(च) स्वामियों द्वारा बिरोजा निस्सारण के लिए, हिमाचल प्रदेश बिरोजा तथा बिरोजा उत्पाद व्यापार विनियमन अधिनियम, 1981 के उपबन्ध तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए नियम लागू होंगे ।

5. **धारा 8 तथा 9 के अधीन नोटिस का जारी किया जाना**.—(क) धारा 8 तथा 9 के अधीन नोटिस ज़िलाधीश द्वारा परिशिष्ट (1) में दिए गए प्रपत्र में दिया जायेगा । यह नोटिस क्षेत्र की स्थानीय भाषा में होगा और सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा तामील करवाया जायेगा।

(ख) धारा 8 और 9 के अधीन दिए गए ऐसे नोटिस में समाविष्ट आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति आवश्यक तथ्यों सहित आक्षेपों का नोटिस जिलाधीश को दे सकता है। अन्तिम आदेश पारित करने से पूर्व ज़िलाधीश तकनीकी पहलुओं के सम्बन्ध में वन मण्डलाधिकारी से परामर्श करेगा।

(ग) धारा 8 और 9 के अन्तर्गत जारी समस्त आदेश भू-स्वामियों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जायेंगे। आदेशों की प्रतियां सहज दृश्य स्थानों पर भी प्रदर्शित की जायेंगी।

(घ) धारा 9 के अधीन किए गए आक्षेपों पर आदेश करते समय ज़िलाधीश निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा:—

(1) समस्त जलागम क्षेत्र के प्रबन्ध की आवश्यकता।
(2) कथित क्षेत्र में भू-कटाव के परिणामस्वरूप निकटस्थ भूमि की सम्भावी क्षति।
(3) भू-गत जल स्तर पर (भू-कटाव का) प्रभाव।
(4) भू-कटाव के कारण जलाशयों में या निकटस्थ क्षेत्रों में माद्य की भराई।
(5) क्षेत्रों के अवक्रमण के कारण किसी भी प्रकार के खतरे से संचार लाइनों की अभिरक्षा तथा रक्षा की आवश्यकता।
(6) वन संरक्षण परिवेश तथा परिस्थितिक स्तर में सुधार की आवश्यकता।

6. **निष्पादित किए जाने वाले कार्यों पर के नियन्त्रण के विनियमित करने के उपाय**.—(1) धारा 9(1) तथा 9 (2) के अधीन किसी भी भूमि के सम्बन्ध में नोटिस/अधिसूचना जारी करने से पूर्व सहायक अरण्यपाल के पद से अन्यून के अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी।

(2) कथित अधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण करेगा और अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखेगा :—

(1) कार्य निष्पादित किए जाने की आवश्यकता और ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित करना;
(2) आबादी सहित निकटस्थ सम्पदा को नदी/चो द्वारा पहुंचाई जा रही क्षति का स्वरूप;
(3) क्षति को कम करन के लिए नालियों द्वारा नदी पानी के बहाव को नियन्त्रित करने की आवश्यकता;
(4) नदी अथवा चो तल में आने वाली भूमि को कृषि योग्य बनाने की वांछनीयता और सम्भावना;
(5) अन्य कार्यों के निष्पादन की वांछनीयता तथा संभाव्यता और ऐसे कार्यों के निष्पादन के उपाय;
(6) कथित अधिकारी उपचार के उपायों के स्वरूप और सीमा को दर्शाते हुए प्रस्ताव रखेगा;
(7) ऐसी जांच पड़ताल पूर्ण होने पर जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी की सिफारिशों सहित सम्बन्धित वन अरण्यपाल के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्र के ज़िलाधीश को उचित आदेशों हेतु प्रस्तुत की जाएगी ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

परिशिष्ट (1)

कार्यालय जिलाधीश.....जिला

नोटिस.....(सूचना अथवा चेतावनी)

हिमाचल प्रदेश भू-संरक्षण अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम संख्यांक 28) की धारा 8 तथा 9 के अधीन.....तहसील के निम्नलिखित क्षेत्र को धारा 4, 5 तथा 6 (मिटा दें जो लागू नहीं) के अधीन की गई अधिसूचना संख्या.....दिनांक..... (प्रति संलग्न) से निषिद्ध किया जाता है और कथित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निर्वन्धन और अवरोध अधिरोपित किए जाते हैं।

क्षेत्र का विवरण

ग्राम का नाम.....

हदबस्त संख्या.....

खसरा संख्या.....

2. ये निर्वन्धन..... से ..... तक लागू रहेंगे।

3. अतः हिमाचल प्रदेश भू-संरक्षण अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम संख्यांक 28) की धारा 8 और 9 के अधीन यह नोटिस प्रत्येक उस सम्बन्धित व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसको इन निर्वन्धनों/अवरोधों/निषेदों के विरुद्ध कोई आक्षेप या कोई दावा हो जिन्हें लिखित या मौखिक रूप में दिनांक..... से पूर्व दायर किया जा सकता है। वह उसे स्वीकार्य प्रतिकर के ढंग और स्वरूप की सूचना भी देगा।

4. ऊपर उल्लिखित क्षेत्र स्थल पर सीमांकित कर दिया गया है और इसकी परिसीमाएं या अवस्थिति ग्राम सरपंच/लम्बरदार अथवा सम्बन्धित दूसरे अधिकारी से अभिनिश्चित की जा सकती है। आवश्यक सूचना हल्का पटवारी से भी प्राप्त की जा सकती है।

जिलाधीश.....

जिला.....

[Authoritative text of English version of this Department Notification No. Fts (A)3-1/81, dated 1st June, 1983 is published under Article 348 (3) of the Constitution of India for the general information of the public.]

FOREST FARMING AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st June, 1983

No. Fts. (A) 3-1/81.—In exercise of the powers conferred under section 21 of the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978 (Act No. 28 of 1978), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for purposes of carrying into effect the provisions of the said Act:—

THE HIMACHAL PRADESH LAND PRESERVATION RULES, 1983

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Land Preservation Rules, 1983.

(*ii*) These rules shall come into force with immediate effect.

2. *Definitions.*—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978 (28 of 1978);
(*b*) "section" means the section of the Act;
(*c*) "Chief Conservator of Forests" means the Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh;
(*d*) "Divisional Forest Officer" means the Forest Officer in charge of a territorial Forest Division;
(*e*) "Range Officer" means the Forest Officer in charge of a territorial Forest Range;
(*f*) "Forest Guard" means the Forest Guard in charge of a territorial Forest beat;
(*g*) "Form" means a form appended to these rules;
(*h*) "term" *bonafide* domestic or agricultural purposes shall not include :—

(*i*) removal and use of timber for construction work, or any other forest produce other than grass outside the Revenue Estate in which the land is situated;
(*ii*) use of firewood for burning of bricks, manufacture of Katha or any other manufacturing process except burning of charcoal for domestic local use; and

(*i*) all other words and expressions used herein but not defined and defined in the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978, have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. *Procedure to be adopted for holding enquiry under section 7 before issuing a notification/ order under section 4, 5 and 6.*—(1) Before issuing a notification in respect of any area under section 4, 5 or 6, an enquiry shall be held by a Gazetted Officer nominated by the Chief Conservator of Forests to ascertain the facts for issue of such notification.

(2) The said officer shall visit the area(s) to be notified and among other things, may examine the following aspects:—

(*i*) The situation of the area.
(*ii*) Configuration and condition of the area.
(*iii*) Present land use practices and their effect on general sub-soil water table.
(*iv*) Extent and degree of water and wind erosion and reasons of erosion.
(*v*) Attitude of the public regarding imposing of restrictions.
(*vi*) Whether the existing management is adequate to maintain and improve the soil status or not.

(3) And or base his enquiry on the overall damage caused to property, land and tree growth which may have been assessed as a consequence of any study made in regard to damage caused due to floods or other natural calamities.

(4) After the completion of enquiry, the Chief Conservator of Forests shall forward the same to the State Government with his recommendations.

(5) The State Government after satisfying itself may issue a notification, to temporarily regulate, restrict or prohibit any action, under section 4, 5 or 6, for a period not more than 30 years.

4. *Procedure for issue of permits for removal of Forest Produce from area closed under sections* 4 & 5:

(1) For Bona fide **Domestic and Agricultural Purposes:**

(*a*) There will be no restriction on the use of forest produce for *bona fide* domestic purposes of fuel and fodder.

(*b*) The owners for their *bona fide* domestic and agricultural use may fell trees as per procedure and extent of trees specified under notifications issued under section 4 or 5 of the Act.

(*c*) The trees allowed for felling for *bona fide* domestic and agricultural use will be marked as per instructions of Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh.

(*d*) The owners shall send written information regarding the trees felled without permission to the Range Officer concerned through beat Guard. Range Officer shall send a copy of such information to Divisional Forest Officer for his record.

(*e*) The beat Guard shall maintain a proper record on a Register of all such fellings done for domestic and agricultural use with or without permission as per notification issued under section 4 and 5 shall affix his hammer mark on such felled stumps. The produce of such trees may be checked by him from time to time till it is consumed for the purposes for which it has been converted. No export of any part of the produce of such trees will be allowed.

(2) For Sale :

(*a*) The trees of all species for sale shall be felled by the owners in accordance with the felling cycle prescribed *vide* notification issued under section 4 of the Act.

(*b*) Permission for removal of trees for sale shall be accorded by various functionaries as per limit and extent prescribed under above referred notification.

(*c*) Application of felling of trees and removal of forest produce shall be submitted to the Divisional Forest Officer concerned by the owners.

(*d*) The area from where the trees are intended to be sold by the owner shall be demarcated by the Revenue Officer not below the rank of Naib-Tehsildar in the presence of Range Officer of the area concerned and nominee of the Agent; provided that where Naib-Tehsildar is not posted, the demarcation of the area shall be carried out by Field Kanungo.

(*e*) The silvicultural marking of the trees shall be done as per rules framed/instructions issued by the Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh from time to time. No clear felling of the area shall be allowed even for purpose of raising orchards.

(*f*) The Divisional Forest Officer shall issue permission for felling of trees and permit for collection or removal of forest produce.

(*g*) While issuing felling permission/permits, Divisional Forest Officer may impose such restrictions/conditions as he may consider necessary in the interest of forest conservancy and misuse of forest produce so extracted.

(*h*) The Divisional Forest Officer while issuing the permission for felling of trees may indicate the number and species of the plants to be planted as compensatory plantation as provided under rule 4 (*c*).

(*i*) The provisions of H. P. Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1982 and the rules made thereunder shall apply as such for the sale of trees.

(3) Compensatory Plantations:

(*a*) Any person(s) felling the trees either for domestic or agricultural use or for sale shall be required to plant at least 3 trees for one tree felled. In case, however, a fruit orchard is planted in such area, it shall be planted according to the norms laid down by the State Horticulture Department for complete stocking of the area. The success of such plants planted shall be the responsibility of the owners which shall be checked frequently by the staff of Forest/Horticulture Department.

(*b*) Divisional Forest Officer may require the owner to deposit such amount not exceeding Rs. 3.00 per plant (to be planted) for carrying out compensatory planting so that plants could be planted if the owner(s) fails to plant 3 plants for every tree felled, within one year of felling.

(4) No tree shall be granted to such owner(s) from the Government forests at the right-holders rate for the next 10 years who sell trees from their private lands.

(5) (*a*) The extraction of resin will be undertaken with the written permission of the Divisional Forest Officer concerned in accordance with the instructions issued by the Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh from time to time laying down the period of extraction, number of blazes, length, width and depth of blazes and other related matters.

(*b*) No rasin so extracted shall be removed/exported by any person from the area under tapping without obtaining an export permit from the Divisional Forest Officer concerned as per rules framed.

(*c*) The provisions of Himachal Pradesh Resin and Resin Products (Regulation of Trade) Act, 1981 and rules made thereunder shall apply as such for the extraction of resin by owners.

5. *Issue of notice under section* 8 *and* 9.—(1) The notice under section 8 & 9 shall be issued by the Deputy Commissioner in the form given in Annexure-I. This notice shall be in the local language of the area and will be served through Gram Panchayats concerned.

(2) Any person aggrieved by an order contained in such a notice given under section 8 & 9 may serve a notice of his objection, along with necessary evidence, to the Deputy Commissioner. Before passing final orders, the Deputy Commissioner shall consult the Divisional Forest Officer regarding technical aspects.

(3) Every order issued under section 8 & 9 shall be sent to the landowners through registered post. Copies of the order shall also be displayed at conspicuous places.

(4) The Deputy Commissioner while making an order on objections brought under section 9 shall be guided by the following:—

(*i*) Necessity of treatment of catchment area as a whole;
(*ii*) Potential damage to the adjoining lands as a result of soil erosion in the said area;
(*iii*) Effect (of soil erosion) on the sub-soil water table;
(*iv*) Siltation in water reserviors within or aojoining the area due to soil erosion;
(*v*) Need for safe guarding and protection of lines of communication against any danger due to degradation of areas;
(*vi*) Need for improvement in forest conservancy environment and ecological status.

6. *Measures to regulate control over works to be executed.*—(1) Before issuing a notice/ notification in respect of any land under section (9)(1) and 9 (2), an enquiry by an officer not below the rank of Assistant Conservator of Forests shall be held.

(2) The said officer shall visit the area and among other things shall study the following aspects:—

(*i*) The necessity of getting the works executed and fixing the time limit for the execution of such works;
(*ii*) The nature of damage being done to the adjoining property including habitation by the stream/ cho;
(*iii*) Necessity of regulating the flow of water by draining the streams to minimise the damage ;

(*iv*) Desirability and feasibility of reclaiming the land in the stream/cho bed;
(*v*) Desirability and feasibility of execution of other works and measures for such execution of works.

(3) The said officer shall make proposals indicating the nature and extent of remedial measures.

(4) After completion of such an enquiry, the enquiry report along with recommendations of the enquiry officer shall be submitted to the Deputy Commissioner of the area concerned through the concerned Conservator of Forests for appropriate orders.

Sd/-
Secretary.

ANNEXURE I

Office of Deputy Commissioner..... District Himachal Pradesh

Notice: Information or Warning.

Under sections 8 and 9 of the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978 (Act No. 28 of 1978) the following area of Village..... Tehsil..... is closed under section 4, 5 and 6 (delete which is not applicable) in accordance with Notification No .....dated..... (copy enclosed) and restrictions and restraints as specified in the aforesaid notification are imposed.

Description of area:

Name of Village.
Habdast No.
Khasra No.

2. These restrictions shall remain in force from .....to.....

3. Therefore, under section 8 and 9 of the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978 (Act No. 28 of 1978) this notice is being issued to every such person who has objection/claim against these restrictions/restraints which can be filed by him in writing or orally before .....He shall also inform the mode and type of compensation acceptable to him.

4. The above mentioned area has been demarcated on the spot and its boundaries/location can be ascertained from village Sarpanch/Lumberdar or other concerned official. Necessary information may also be obtained from halqua Patwari as well.

TOURISM DEPARTMENT

STANDING ORDERS

Shimla-2, the 6th August, 1983

No. 4-71/83-TSM(Sectt).—In pursuance of rule 26 and 27 of the Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh, 1971, and in supersession of all previous orders in this behalf, the Minister-in-charge, Tourism Department, Himachal Pradesh directs that cases and matter relating to the Department, shall ordinarily be disposed of in the manner indicated in the enclosed Annexure-I and II.

2. In absence of the Minister-in-charge, the Minister of State (Tourism)/Deputy Minister (Tourism) or in his absence the Secretary (Tourism) or in his absence the Deputy Secretary (Tourism), Himachal Pradesh will finally dispose of cases of extreme urgency. Such cases will however, be shown to the Minister-in-charge on his arrival at the headquarters.

R. K. ANAND,
Secretary,

ANNEXURE I

LIST OF CASES TO BE DISPOSED OF AT MINISTER'S LEVEL

Sr. No.	Nature of cases
1.	Cases mentioned in rules 14, 15, 16, 55 of the Rules of Business to be submitted to the C. M./Governor.
2.	*Assembly/Parliament Business*:
	(*i*) Approval of replies of Vidhan Sabha questions/resolutions;
	(*ii*) Lok Sabha/Rajya Sabha questions (only important cases involving principles of policy);
	(*iii*) Adjournment and Cut Motions;
	(*iv*) Report about action taken on the assurances given by the Minister on the floor of the Legislature;
	(*v*) Report of Public Accounts Committee and Estimates Committee when ripe for fin l decision;
	(*vi*) Matters concerning the Vidhan Sabha Committee on Petition, Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and follow up thereon; and
	(*vii*) Papers to be laid down on the Table of the House and correspondence regarding the House Committee thereon.
3.	*Legal Matters*:
	(*i*) Framing of Rules under various Acts;
	(*ii*) Acquisition of lands/buildings for public purpose; and
	(*iii*) Bills (including Private Members Bills), Acts, Rules, Regulations, Manuals, Codes, Executive Instructions (Evolution, Assessment and Interpretation etc.).
4.	*Organisation*:
	(*i*) Creation/abolition of posts, offices, field institutions;
	(*ii*) Appointment of Committee/Boards/Commissions of Enquiry and their report;
	(*iii*) Delegation of International Organisations, Committees/Conferences; and
	(*iv*) Substantial Reforms in the Department.
5.	*Policy and Programme*:
	(*i*) Deviation from the existing policy;
	(*ii*) Formulation of new Programmes and Projects and setting up of new institutions etc; and
	(*iii*) Substantial changes in the scheme already approved.

6. *Establishment:*

(*i*) Creation/abolition of posts and fixation of Cadre;
(*ii*) Framing of Service Rules, Relaxation of condition thereof;
(*iii*) Annual Statements of appointments made without consulting Service Commission;
(*iv*) Sponsoring of inservice candidates for training abroad;
(*v*) Appeals and Petitions of Class I and II Officers;
(*vi*) Appointment, extension of probationary period, confirmation, transfer, withholding of efficiency bars, deputations, pension, seniority and re-employment of Class-I Officers;
(*vii*) References to Vigilance Department in case of Gazetted Officers and inquiries against them;
(*viii*) Memorials submitted by employees that requires Minister's order under the rules.
(*ix*) Deputation cases of all employees;
(*x*) Confidential Reports:—
(*a*) Class-I Officers;
(*b*) Class-II Officers at the Headquarters;
(*xi*) Departmental Promotion Committees/Selection Committees, constitution and proceedings in respect of Class I Officers;
(*xii*) Retention in service after superannuation of Class-I Officers;
(*xiii*) Disciplinary proceedings against Class-I and Class-II Officers (Major Penalties);
(*xiv*) Cases of appeals against compulsory retirement/dismissal of Class-III employees;
(*xv*) Cases of re-employment or condonation of break in service of class II and IV officials; and
(*xvi*) Institution or withdrawal of civil or criminal proceedings against Class-II, III and IV officials and payment from the State Revenue or damages suits brought up against Government servants.

7. *Budget, Accounts and Financial Matters;*

(*i*) Grant-in-aid above Rs. 1,00.000/- while no Rules have been framed/Share Capital;
(*ii*) Audit paras;
(*iii*) Governor's address and budget speech;
(*iv*) Budget proposals and supplementary grants;
(*v*) Recovery of revenue;
(*vi*) Contingency fund and advances cases;
(*vii*) Proposal involving the alienation either temporary or permanent of sale, grant of lease of Government property less than 25,000/- in value of the abondonment or reduction of revenue in accordance with Rules or with a general scheme already approved by the Council of Ministers;
(*viii*) Expenditure from discretionary grants, contributions etc;
(*ix*) Evolution of patterns of delegation of financial powers and to subordinate authorities;
(*x*) Write off of irrecoverable loans and advances and remission of loans and advances above Rs. 5,000/-; and
(*xi*) Write off losses, stores etc. above Rs. 20,000/-.

8. *General Matters:*

(*i*) All policy matters received from and referred to Government;
(*ii*) Annual Administrative Report and Annual Accounts of the Department;
(*iii*) Re-organisation cases including re-distribution of functions;
(*iv*) State level joint consultative committee; and
(*v*) Grievances of public relating to the working of the Department and any other cases that the Minister-in-charge may like to see or the Secretary may like to bring to his notice.

ANNEXURE II

LIST OF CASES TO BE DISPOSED OF AT THE LEVEL OF THE SECRETARY (TOURISM) AND BELOW

Sr. No.	Nature of cases	Level at which to be disposed of
1	2	3
1.	*Legal Matters*:	
	(*i*) Writ petitions	.. *Secretary.*
	(*ii*) Appeals against judgments	.. *Secretary.*
	(*iii*) Notice u/s 80 C.P.C.	.. *Dy. Secretary.*
2.	*Policy and Programme*:	
	(*i*) Inclusion of new schemes in the schedule of new expenditure at the Budget stage	.. *Secretary.*
	(*ii*) Annual reports on the working of Department	*Secretary.*
3.	*Establishment*:	
	(*i*) Conversion of temporary posts into permanent ones	.. *Secretary.*
	(*ii*) Orders for placing requisitions for recruitment	.. *Secretary.*
	(*iii*) Sponsoring of inservice candidate for training in India:—	
	(*a*) Class I and II Officers	.. *Secretary.*
	(*b*) Class III officials	.. *Dy. Secretary.*
	(*iv*) Appeal/Petitions of:—	
	(*a*) Class III officials other than dismissal/compulsory retirement	.. *Secretary.*
	(*b*) Appointment, confirmation, transfer, with-holding of efficiency bars, pension, seniority and re-employment of Class IV officials	.. *Secretary.*
	(*v*) *Crossing of Efficiency Bar*: Class-I and II Officers	.. *Secretary.*
	(*vi*) Confidential Reports of Class II Officers other than the Head-quarters	.. *Secretary.*
	(*vii*) Grant of advance increments with the concurrence of the F. D.	.. *Secretary.*
	(*viii*) Departmental Promotion Committee/Selection Committee—Constitution and proceedings in respect of Class II and Class III Officers	.. *Secretary.*
	(*ix*) Retention in service after superannuation of Class II and Class III Officers	.. *Secretary.*
	(*x*) Extension of Temporary posts	.. *Dy. Secretary.*
	(*xi*) Sanction of special pay	.. *Dy. Secretary.*
	(*xii*) Sanction of G. P. Fund Advance	.. *Dy. Secretary.*
	(*xiii*) Disciplinary proceedings against Class II Officers (Mnor penalties)	*Secretary.*
4.	*Budget, Accounts and Financial Matters*	
	(*i*) Budget Estimates, continued items including standing charges	.. *Secretary.*
	(*ii*) Budget Estimates (Really New Schemes)	.. *Secretary.*
	(*iii*) Administrative approval and Technical sanction of New Schemes	.. *Secretary.*
	(*iv*) *Contingent sanctions*:—	
	(*a*) above Rs 50,000/-	.. *Secretary.*
	(*b*) upto Rs. 50,000/-	.. *Dy. Secretary.*
	Functional Buildings: above Rs. 6,00,000/-	.. *Secretary.*
	upto Rs. 6,00,000/-	.. *Dy. Secretary.*

1	2	3
(v)	*Woks including repairs*:	
	Other than functional buildings above Rs. 50,000/- upto Rs. 50,000/-	.. *Secretary.*
(vi)	*Grant-in-aid*:	.. *Dy. Secretary.*
(i)	Where Rules have been approved and framed	.. *Secretary.*
(ii)	*Other cases*:	
	Between Rs. 50 ,000/- and Rs. 1,00,000/-	.. *Secretary.*
(vii)	Write off cases of irrecoverable loans, advances and remission of loans and advances upto Rs. 5,000/-	.. *Secretary.*
(viii)	Write off losses off stores etc. below Rs. 20,000/-	.. *Secretary.*

SCHEDULE N

TYPES OF CASES TO BE DISPOSED OF AT THE LEVEL OF THE SECTION OFFICER (TOURISM)

1. Routine references/reminders regarding all cases of appointments/confirmation/promotion/transfers/revision/disciplinary action/compulsory retirement and pension of Gazetted Officers of the Department/Annual A.C.R.s of the Heads of Departments.

2. Routine references regarding Budget.

3. Information/Receipts.

4. Routine references regarding purchase/hiring of typewriters/hiring of buildings/advances from G. P. F. and matters relating to T. A.

5. Casual leave of the staff in the section.

सामान्य प्रशासन विभाग

(सी-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 17 अगस्त, 1983

सं0 3-34/72-जी0 ए0 सी0.—पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं0 6) की धारा 6 के अन्तर्गत उसमें विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, ऊना, जिला की हरोली उप-तहसील के पटवार वृत्तों नामतः पन्जावर, खड्, पण्डोगा, भदसाली और सलोह को उक्त उप-तहसील से सहर्ष अपवर्जित करते हैं तथा इन्हें ऊना तहसील, जिला ऊना में तुरन्त सम्मिलित करते हैं।

आदेश द्वारा,
के. सी. पाण्डेय,
मुख्य सचिव।

[*Authoritative English text of this Government Notification No.* 3-34/72-*GAC, dated the* 17*th August*, 1983 *as required under Article* 348 (3) *af the Constitution of India.*]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(C-SECTION)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th August, 1983

No. 3-34/72-G.A.C.—In exercise of the powers vested in him under section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) and section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to exclude Panjawar, Khad, Pandoga, Bhadsali and Saloh patwar circles from Haroli sub-tehsil of the Una district and to include the said patwar circles in Una tehsil of the Una district with immediate effect.

By order,
K. C. PANDEYA,
Chief Secretary.

गृह विभाग

(ख-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 17 अगस्त, 1983

संख्या गृह-II(ई) 5-2/76.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 304 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल निदेश देते हैं कि हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायालय द्वारा अधिसूचना संख्या एच0एच0सी0 18-4/74 दिनांक 14 मार्च, 1983 द्वारा यथा अधिसूचित "अभियुक्त को सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता नियम, 1981" इस अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से हिमाचल प्रदेश के अन्य न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे सैशन न्यायालय के सम्बन्ध में विचारण के लिए लागू होते हैं।

आदेश द्वारा,
के0 सी0 पाण्डेय,
मुख्य सचिव।

[In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the publication of the following English text of notification No. Home-II (E) 5-2/76, dated 17-8-1983.]

HOME DEPRATMENT

(B-SECTION)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th August, 1983

No. Home-II (E) 5-2/76.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 304 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to direct that the Himachal Pradesh Legal Aid to Accused at State Expense Rules, 1981, as notified by the High Court of Himachal Pradesh *vide* notification No. HHC. Admn. 18-4/74, dated the 14th March, 1983, shall apply to trials before other courts in Himachal Pradesh as they apply in relation to trials before court of Session, with effect from the date of publication of this notification in the Himachal Pradesh Rajpatra.

By order,
K. C. PANDEYA,
Chief Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हि0प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।